www.adbhutsamachar.com

अद्भुत समाचार

वर्ष – 15 | अंक–42 | RNI-No. : UPHIN/2011/43806 | लखनऊ,शनिवार 10 जनवरी, 2026 | प्रातः कालीन संस्करण | (हिन्दी दैनिक) | पृष्ठ–4 | मूल्य 1 रुपया

सीएम योगी ने ईवी प्लांट का किया उद्घाटन

बोले- अब यूपी अपनी क्षमताओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते आठ वर्षों में यूपी सिर्फ असीमित क्षमताओं वाला प्रदेश ही नहीं रहा बल्कि क्षमताओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश आज निवेशकों की पसंद में पहले स्थान पर है।

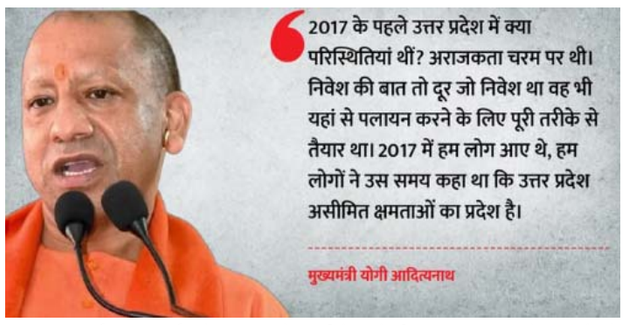

लखनऊ 09 जनवरी (एजेंसी)मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व रक्षामंत्री ने लखनऊ में अशोक लीलैंड के इलेक्ट्रिक वाहन के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने फैक्ट्री का उद्घाटन करने के बाद ई–बस में सफर भी किया। फैक्ट्री का निर्माण सरोजनी नगर इलाके में करीब 70 एकड़ में किया गया है। यहां पर ई–बस, ई–ट्रेवलर और ई–लोडिंग वाहन बनाए जाएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह हमारे लिए महत्वपूर्ण अवसर है। इसके लिए मैं हिंदुजा परिवार को बधाई देता हूं। यह निवेश बताता है कि यूपी में बीते आठ वर्षों में क्या परिवर्तन हुए हैं। प्रदेश के हर जिले में निवेश हो रहा है। जो कि बताता है कि अब यूपी अनलिमिटेड पोटेंशियल का ही प्रदेश नहीं बल्कि पोटेंशियल को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश बन चुका है।आज यूपी न सिर्फ देश के बल्कि दुनिया के निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य बन चुका है। यही कारण है कि यूपी में निवेश के लिए 45 लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। प्रदेश में बीते आठ वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो काम हुआ है यही कारण है कि आज देश के 55 फीसदी एक्सप्रेस वे यूपी में हैं। प्रदेश में रैपिड रेल बनाई जा रही है। आज प्रदेश में 18 हजार स्टार्टअप काम कर रहे हैं।इस मौके पर भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि यह सिर्फ प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए आत्मनिर्भर भारत और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में बड़ा कदम है। यह भारत के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।इस मौके पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि योगी जी जिस तरह से यूपी को चला रहे हैं। उससे सहज ही प्रदेश की रेटिंग एक्सीलेंट कही जा सकती है। अशोक लीलैंड कंपनी की इस ईवी फैक्टरी का उद्घाटन प्रदेश के औद्योगीकरण की दिशा में मील का पत्थर है।उन्होंने कहा कि मैं लखनऊ से सांसद हूं पर अगर मैं लखनऊ का न भी होता तो भी यह शहर मुझे उतना ही प्रिय होता जितना कि आज है । पहले जिस यूपी को खराब कानून व्यवस्था और दंगों से जोड़कर देखा जाता था वो अब निवेश के क्षेत्र में अपनी जगह बना रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। प्रदेश में निवेश होने से यहां के युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार मिल सकेगा। रक्षामंत्री ने कहा कि अब यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है। अब भारत एक कमजोर देश नहीं बल्कि अपने हथियार खुद बनाता है और इस कार्य में यूपी बढ़–चढ़कर अपनी भूमिका निभा रहा है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई देता हूं। प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था के क्षेत्र में सुधार हुआ है वो अपने आप में एक मिसाल है।

रक्षा गलियारो बनेगा लखनऊ, राजनाथ सिंह बोले- आत्मनिर्भर भारत से बढ़ी देश की ताकत

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊमें अशोक लेलैंड संयंत्र का दौरा कर सैन्य वाहनों का निरीक्षण किया और उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारे के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा कि देश का घरेलू रक्षा उत्पादन 1.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो भारत की बढ़ती औद्योगिक क्षमता को दर्शाता है।

नई दिल्ली 09 जनवरी (एजेंसी)रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को लखनऊ में अशोक लेलैंड के विनिर्माण संयंत्र का दौरा किया। इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित अपने दौरे के दौरान, उन्होंने संयंत्र में निर्मित हल्के सामरिक वाहन, मानवरहित जमीनी वाहन, बारूदी सुरंग से सुरक्षित वाहन और लॉजिस्टिक ड्रोन के उत्पादन की समीक्षा की। इस दौरे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। अपने उद्घाटन भाषण में रक्षा मंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में सरकार ने एक रक्षा गलियारा स्थापित किया है। सशस्त्र बलों से संबंधित हथियार और गोला–बारूद अब लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, चित्रकूट और अलीगढ़ में निर्मित किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि 34,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश पहले ही हो चुका है। बड़ी कंपनियां आ रही हैं और कारखाने स्थापित कर रही हैं। इससे स्थानीय लोगों को भी प्रत्यक्ष लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में ब्रह्मोस फैक्ट्री भी स्थापित की गई है, जिसका प्रभाव आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा होगा। भारत अब अपने हथियार स्वयं बना रहा है। इस सामरिक सुधार में उत्तर प्रदेश लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि, "उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अलग नीति बनाई हैय एयरोस्पेस और रक्षा इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति।

सनसनीखेज खुलासा रु इंसानों के ब्लड बैग में भरा मिला 1,000 लीटर जानवरों का खून, अधिकारी हैरान

हैदराबाद09 जनवरी (एजेंसी) तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के काचीगुडा इलाके से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए हैं। यहाँ स्थित एक इंपोर्ट–एक्सपोर्ट फर्म पर ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन (ष्ठष्ट्र) द्वारा की गई छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में जानवरों का खून बरामद किया गया है। अधिकारियों को मौके से करीब 1,000 लीटर खून मिला है, जिसे बकरियों और भेड़ों से गैर–कानूनी तरीके से इकत्रा किया गया था। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जानवरों के इस खून को उन विशेष ब्लड बैग्स में पैक करके रखा गया था, जो अस्पतालों में इंसानों का खून सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।सेंट्रल ड्रग कंट्रोल के अधिकारियों ने हैदराबाद पुलिस और राज्य ड्रग कंट्रोल टीम के साथ मिलकर एक गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। फर्म के भीतर का नजारा देखकर रेड मारने गए वरिष्ठ अधिकारी भी दंग रह गए। जांच के दौरान परिसर से न केवल भारी मात्रा में खून मिला, बल्कि इसकी पैकेजिंग और प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले कई अत्याधुनिक उपकरण भी बरामद हुए हैं। टीम ने मौके से एक ऑटोक्लेव मशीन, एक लैमिनार एयर फ्लो यूनिट, 110 भरे हुए ब्लड बैग और लगभग 60 खाली ब्लड बैग जब्त किए हैं।

म्यांमार बार्डर पर एनसीबी का बड़ा एक्शन, 15 करोड़ की हेरोइन जब्तय साबुन के डिब्बों में छिपाकर ला रहे 2 तस्कर गिरफ्तार

इंफाल 09 जनवरी (एजेंसी)। भारत–म्यांमार सीमा पर नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (ह्नष्टक्च) ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। एनसीबी की इंफाल जोनल यूनिट ने असम राइफल्स के साथ मिलकर चलाए गए एक संयुक्त अभियान में 7.312 किलो हाई–ग्रेड हेरोइन जब्त की है। अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में इस खेप की कीमत करीब 15 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस कार्रवाई में दो अंतरराष्ट्रीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है, जो म्यांमार से मणिपुर के रास्ते ड्रग्स सप्लाई करने वाले एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे।एनसीबी को खुफिया जानकारी मिली थी कि 7 जनवरी 2026 को इंडो–म्यांमार सीमा के पास से ड्रग्स की एक बड़ी खेप गुजरने वाली है। इसी आधार पर टीम ने एक बोलेरो वाहन को रोका। जब गाड़ी की बारीकी से तलाशी ली गई, तो अधिकारी भी हैरान रह गए।

तमिलनाडू में इंडिया गठबंधन में रार?

कार्ति चिदंबरम ने सत्ता में हिस्सेदारी पर दिया बड़ा बयान

तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले, कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने सत्ता-साझाकरण की मांगों को स्वाभाविक बताया, यह इंगित करते हुए कि गठबंधन में सहयोगी दलों की सरकार में भागीदारी की आकांक्षा वैध है। उन्होंने डीएमके के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर जोर दिया, जो राज्य में चुनावी रणनीति और सीटों के बंटवारे पर भविष्य की चर्चाओं का संकेत देता है।

नई दिल्ली 09 जनवरी (एजेंसी)आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले सत्ता–साझाकरण की मांगों के बीच, कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने गुरुवार को कहा कि चुनाव में भाग लेने वाली प्रत्येक राजनीतिक पार्टी के लिए अपने प्रतिनिधियों की जीत और सरकार में भागीदारी देखना स्वाभाविक है। चिदंबरम ने एएनआई से कहा, ष्चुनाव लड़ने वाली प्रत्येक राजनीतिक पार्टी चाहती है कि उसके अधिक से अधिक प्रतिनिधि चुनाव जीतें, और यदि वे चुनाव जीतते हैं, तो यदि अवसर मिलता है, तो राजनीतिक पार्टी स्वाभाविक रूप से सरकार में भागीदारी करना चाहती है। यही राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य है।चिदंबरम ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम (डीएमके) के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा बनी हुई है। चिदंबरम ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। हम गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, और डीएमके भारत गठबंधन का हिस्सा है। तमिलनाडु में, डीएमके गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, और हम तमिलनाडु में गठबंधन का हिस्सा हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की डीएमके के खिलाफ की गई टिप्पणियों को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को नष्ट नहीं किया जा सकता। यह जनता पर निर्भर करता है कि वे उसका समर्थन करें या न करें।तमिलगा वेट्री कजगम (टीवीके) प्रमुख और अभिनेता विजय की फिल्म श्जना नायकनश के सेंसर प्रमाणन को लेकर बनी अनिश्चितता पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि देरी का कारण सेंसर बोर्ड को ही बताना चाहिए। चिदंबरम ने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैंने बस अखबार में पढ़ा है। यह एक प्रक्रिया है। यह उनके और सेंसर बोर्ड के बीच का मामला है। इस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। आवेदन समय पर जमा करने के बावजूद देरी क्यों हो रही है, यह बताना पूरी तरह से सेंसर बोर्ड पर निर्भर है।इससे पहले, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने राज्य में इंडिया ब्लॉक के भीतर दरार की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस और डीएमके मजबूती से एकजुट हैं और अपनी दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्ध हैं। इस बीच, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम (एआईएडीएमके) के महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने राजधानी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें तमिलनाडु की मौजूदा

बंगाल में चुनाव से पहले बड़ा घमासान

दिल्ली में टीएमसी सांसदों की गिरफ्तारी पर ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर हमला

बनर्जी ने दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक विरोध को दबाने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।

नई दिल्ली 09 जनवरी (एजेंसी)पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया। यह प्रदर्शन केंद्रीय एजेंसी द्वारा आई–पीएसी के कार्यालय पर छापेमारी के एक दिन बाद हुआ। बनर्जी ने दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक विरोध को दबाने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में गरिमा और सम्मान पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, और इस बात पर जोर दिया कि सत्ता में बैठे लोग नागरिकों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ मनमाने ढंग से व्यवहार नहीं कर सकते। राजधानी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आई–पीएसी कार्यालय पर की गई छापेमारी के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कई सांसदों को हिरासत में लिया गया। एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री बनर्जी ने लिखा कि मैं हमारे सांसदों के साथ किए गए शर्मनाक और अस्वीकार्य व्यवहार की कड़ी निंदा करती हूं। गृह मंत्री के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को सड़कों पर घसीटना कानून प्रवर्तन नहीं है – यह वर्दी में अहंकार है। यह लोकतंत्र है, भाजपा की निजी संपत्ति नहीं। लोकतंत्र सत्ता में बैठे लोगों की सुविधा या आराम पर नहीं चलता। जब भाजपा नेता विरोध करते हैं, तो वे लाल कालीन और विशेष विशेषाधिकारों की उम्मीद करते हैं। जब विपक्षी सांसद अपनी आवाज उठाते हैं, तो उन्हें घसीटा जाता है, हिरासत में लिया जाता है और अपमानित किया जाता है। यह दोहरा मापदंड भाजपा के लोकतंत्र के विचार को उजागर करता है – आज्ञापालन, असहमति नहीं।पोस्ट में लिखा था यह स्पष्ट होना चाहिएरू सम्मान पारस्परिक होता है। आप हमारा सम्मान करते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। आप हमें सड़क पर घसीटेंगे, और हम आपको सहिष्णुता, असहमति और लोकतांत्रिक नैतिकता के संवैधानिक विचार पर वापस खींच लाएंगे।

केटीआर का कांग्रेस पर जमीन हड़पने का आरोप, छात्रों के साथ करेंगे आंदोलन

नई दिल्ली 09 जनवरी (एजेंसी)भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव (केटीआर) ने शुक्रवार को तेलंगाना में कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए उस पर मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (एमएएनयू) की 50 एकड़ जमीन को अवैध रूप से हथियाने का आरोप लगाया। बंजारा हिल्स के नंदी नगर स्थित एक आवास पर एमएएनयू के छात्रों से मुलाकात के बाद उन्होंने ये टिप्पणियां कीं, जहां छात्रों ने उन्हें अपनी चिंताओं से अवगत कराया।छात्रों ने केटीआर को बताया कि वे राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को पहले आवंटित जमीन को वापस लेने के कदम का कड़ा विरोध करते हैं, और कहा कि इस तरह की कार्रवाई से संस्थान के भविष्य के विस्तार और शैक्षणिक विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए केटीआर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार राज्य भर में विश्वविद्यालयों की जमीनों को सुनियोजित तरीके से निशाना बना रही है और ष्लगातार जमीन हड़पने वालेष् की तरह व्यवहार कर रही है।उन्होंने कहा कि एमएएनयू, देश का एकमात्र विशेष उर्दू विश्वविद्यालय और हैदराबाद का गौरव, रियल एस्टेट हितों के लिए जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। केटीआर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान का इस्तेमाल अचल संपत्ति संबंधी जरूरतों के लिए करना चाहती है। इस सरकार ने विश्वविद्यालय की जमीनों पर कब्जा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने पहले भी कृषि विश्वविद्यालय की जमीन को उच्च न्यायालय के नाम पर अधिग्रहित करने के प्रयासों और हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय (एचसीयू) की लगभग 400 एकड़ जमीन पर कब्जा करने के कथित प्रयास का जिक्र किया।केटीआर ने दावा किया कि एचसीयू भूमि मामले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अस्थायी रोक लगाने और 10,000 करोड़ रुपये के भूमि घोटाले पर टिप्पणी करने के बावजूद, न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार ने कोई उचित जांच शुरू की। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र ने तब कड़ा कदम उठाया होता, तो राज्य सरकार एमएएनयू जैसे किसी अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय को निशाना बनाने की हिम्मत नहीं करती।

एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

13 जनवरी को अर्जियों पर सुनवाई

6 जनवरी को, निर्वाचन आयोग ने पीठ को बताया था कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करने का अधिकार और क्षमता उसके पास है, साथ ही यह सुनिश्चित करना संवैधानिक कर्तव्य है कि किसी भी विदेशी को मतदाता के रूप में पंजीकृत न किया जाए।

नई दिल्ली 09 जनवरी (एजेंसी)सुप्रीम कोर्ट ने बिहार समेत कई राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए भारत निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर अंतिम सुनवाई 13 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिन में इन याचिकाओं की सुनवाई तय की थी, लेकिन बाद में कहा कि वह मंगलवार (13 जनवरी) को कार्यवाही फिर से शुरू करेगी। चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी मामले में अपनी दलीलें फिर से पेश करने वाले थे। 6 जनवरी को, निर्वाचन आयोग ने पीठ को बताया था कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करने का अधिकार और क्षमता उसके पास है, साथ ही यह सुनिश्चित करना संवैधानिक कर्तव्य है कि किसी भी विदेशी को मतदाता के रूप में पंजीकृत न किया जाए।चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि कार्यवाही मंगलवार को फिर से शुरू की जाएगी। मामले में चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी को अपने तर्क आगे बढ़ाने थे। 6 जनवरी को चुनाव आयोग ने पीठ को बताया था कि उसके पास मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (ए) करने की शक्ति और क्षमता है, और इसके साथ ही यह संवैधानिक दायित्व भी है कि कोई भी विदेशी मतदाता के रूप में पंजीकृत न हो। इन याचिकाओं में बिहार सहित कई राज्यों में एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के निर्णय को चुनौती दी गई है और इनमें चुनाव आयोग की शक्तियों की सीमा, नागरिकता तथा मतदान के अधिकार से जुड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय उन कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिनमें यह तर्क दिया गया है कि पुनरीक्षण प्रक्रिया अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की संवैधानिक शक्तियों का उल्लंघन कर सकती है।

चाइना को ठेके, डोनाल्ड ट्रम्पपर चुप्पी! खरगे ने कहा

पीएम मोदी की फारेन पालिसी आत्मसमर्पण है

नई दिल्ली 09 जनवरी (एजेंसी)कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकारी ठेकों के लिए चीनी कंपनियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की योजना पर मोदी सरकार की तीखी आलोचना की है। उन्होंने सरकार की विदेश नीति को ष्बेकाबू पेंडुलमष् बताते हुए इसमें असंगति का आरोप लगाया और कहा कि गलवान के शहीदों का अपमान कर चीन के लिए श्लाल कालीनश बिछाया जा रहा है।कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर उन खबरों को लेकर हमला बोला जिनमें कहा गया था कि भारतीय सरकार सरकारी ठेकों के लिए बोली लगाने वाली चीनी कंपनियों पर लगे पांच साल पुराने प्रतिबंध को हटाने की योजना बना रही है। उन्होंने मोदी सरकार की विदेश नीति में असंगति का आरोप लगाया। खरगे ने कहा कि भारत की विदेश नीति एक बेकाबू पेंडुलम की तरह झूलती है और साथ ही भारत की विदेश नीति में असंगति की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा जनता भुगत रही है।प्रधानमंत्री मोदी के ष्मैं देश को झुकने नहीं दूंगाष् वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए खरगे ने कहा कि मौजूदा स्थिति इस दावे के बिल्कुल उलट है। खरगे ने ग पर पोस्ट किया कि मैं देश को झुकने नहीं दूंगा।" आज जो हो रहा है, वह ठीक इसका उल्टा है। दो हालिया उदाहरणरू चीनी कंपनियों पर 5 साल से लगा प्रतिबंध हटाया जा रहा है। गलवान में हमारे बहादुर भारतीय सैनिकों के बलिदान का मोदी ने चीन को क्लीन चिट देकर अपमान किया। अब चीनी कंपनियों के लिए श्लाल कालीनश बिछाकर, वह दिखा रहे हैं कि उनकी श्लाल आंखोंश में श्लाल रंगश कितना गहरा है।कांग्रेस अध्यक्ष ने भारत के रूसी तेल निर्यात पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की टिप्पणियों पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी की भी आलोचना करते हुए इसे आत्मसमर्पण का संकेत बताया।

बांग्लादेश में बर्बरता व दरिंदगी का सिलसिला

बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदायों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। सोमवार 5 जनवरी को देर रात एक हिंदू दुकानदार मोनी चक्रवर्ती की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जो पिछले 24घंटों में इस तरह की दूसरी घटना है। इससे पहले राणा प्रताप बैरागी नाम के युवक को जान से मार डाला। इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है।

आपको बता दें चौबीस घंटे में दो हिन्दुओं को कट्टरपंथी मजहबी हत्यारों ने मौत के घाट उतार दिया था। नरसिंग्दी जिले के पोलाश उपजिला के चोर्सिंदूर बाजार में किराना दुकान चलाने वाले हिंदू व्यापारी मोनी चक्रवर्ती पर अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल मोनी की अस्पताल ले जाते समय ही मौत हो गई। परिवार का कहना है कि मोनी का किसी से कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं था। वह शांत स्वभाव का था। उनकी पत्नी अंतरा मुखर्जी हाउसवाइफ हैं और उनका 12 वर्षीय बेटा अभिक चक्रवर्ती है। इसी दिन जेस्सोर जिले में एक अन्य हिंदू कारोबारी 38 वर्षीय राणा प्रताप बैरागी की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जो एक समाचार पत्र के कार्यवाहक संपादक भी थे।

इन दिनों बांग्लादेश में कट्टरपंथी उन्मादी हिन्दुओं के खिलाफ खून–खराबा कर रहे हैं। बांग्लादेश में जून, 2024 में शेख हसीना की सरकार के विरुद्ध आरक्षण और नौकरियों आदि में भेदभाव जैसे मुद्दों को लेकर छात्रों द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के 3 महीनों बाद अंततः 5 अगस्त, 2024 को शेख हसीना को गद्दी छोड़नी पड़ी और तब से उन्होंने भारत में ही शरण ले रखी है।

शेख हसीना के भारत आने के बाद सेना ने जब मोहम्मद यूनुस को देश की सत्ता सौंप दी तो उम्मीद थी कि शायद वह उदारवादी रवैया अपना कर देश में व्याप्त असंतोष दूर करने और वातावरण सामान्य बनाने में सहायता करेंगे। आशा के विपरीत मो. यूनुस ने देश की पाठ्य पुस्तकों से बंगलादेश के मुक्ति संग्राम और बंग बंधु शेख मजीबुर्रहमान से संबंधित अध्याय निकाल देने का आदेश जारी करके देश के मुक्ति संग्राम का इतिहास मिटाने की कोशिशें शुरू कर दीं और सैकड़ों आतंकवादियों को जमानत देकर या उनके विरुद्ध आरोप वापस लेकर उन्हें जेलों से बाहर कर दिया है।

सेना और कट्टरपंथियों के दबाव में आकर यूनुस प्रशासन ने देश में 12 फरवरी, 2026 को चुनाव करवाने की घोषणा की है। इसके साथ ही यूनुस ने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाकर उसे क्रियात्मक रूप से चुनावों में भाग लेने से रोक दिया है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के अगले ही दिन कट्टरपंथी संगठन इन्कलाब मंच के प्रवक्ता और छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी ने ढाका–8 सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी परंतु इसके अगले ही दिन सरेआम एक मोटरसाइकिल सवार ने उसकी हत्या कर दी।

दरअसल चुनावों के लिए तय तारीख की घोषणा के साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़ गए तथा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दो दिसंबर, 2025 से पिछले लगभग 35 दिनों में बांग्लादेश में कम से कम एक दर्जन हिंदुओं की हत्या की गई है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद द्वारा आज जारी एक बयान के अनुसार, अकेले दिसंबर में सांप्रदायिक हिंसा में कम से कम 51 घटनाएं दर्ज की गईं।स्थानीय मीडिया के अनुसार, 19 दिसंबर को शरत चक्रवर्ती ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर देश में हिंसा पर चिंता जताई थी, जिसमें उन्होंने अपनी जन्मभूमि को मौत की घाटी बताया था। एक चश्मदीद और रिश्तेदार प्रदीप चंद्र बर्मन ने इस हमले को सोची–समझी साजिश बताया। उन्होंने कहा, पहले से दुश्मनी थी.. उन्होंने (हमलावरों ने) उनका मोबाइल फोन या मोटरसाइकिल नहीं छीनी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दो दिसंबर, 2025 को 42 वर्षीय सोने के हिंदू व्यापारी प्रांतोष कर्मकार की रात के समय बांग्लादेश के नरसिंगदी जिले के रायपुरा उपजिला में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दो दिसंबर, 2025 को 35 वर्षीय हिंदू मछली व्यापारी उत्पल सरकार की सुबह के समय फरीदपुर जिले के साल्था उपजिला में बेरहमी से हत्या कर दी गई। सात दिसंबर, 2025 को 1971 के मुक्ति संग्राम के मुक्तिजोद्धा 75 वर्षीय जोगेश चंद्र राय और उनकी पत्नी सुबोर्ना राय की रंगपुर में गला रेतकर हत्या। 12 दिसंबर, 2025 को 18 वर्षीय हिंदू ऑटो रिक्शा ड्राइवर शांतो चंद्र दास कुमिला जिले में मृत पाए गए। उनका गला रेतकर शव मक्के के खेत में फेंक दिया गया था। 18 दिसंबर, 2025 को मैमनसिंह के भलुका में 27 वर्षीय हिंदू गारमेंट वर्कर दीपू चंद्र दास को इस्लामी भीड़ ने पीट–पीटकर मार डाला और 24 दिसंबर, 2025 को राजबाड़ी जिले के 30 वर्षीय हिंदू अमृत मंडल को भीड़ ने पीट–पीटकर मार डाला। उसके खिलाफ कई मामले दर्ज थे।

29 दिसंबर, 2025 को बांग्लादेश के अर्धसैनिक सहायक बल अंसार वाहिनी के हिंदू सदस्य बजेंद्र बिस्वास को मैमनसिंह जिले में फैक्ट्री में साथी नोमान मियां ने गोली मारी। इसके बाद 3 जनवरी, 2026 को शरियतपुर जिले के हिंदू व्यवसायी खोकन चंद्र दास को घर लौटते समय हमलावरों ने रोककर चाकू मारा, फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। उसी दिन बंगलादेश के झिनाइदह में हिंदू विरोधी तत्वों ने एक विधवा हिंदू महिला से सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसे पेड़ से बांध कर बुरी तरह पीटा और उसके बाल भी काट दिए।

5 जनवरी, 2026 का एक अखबार के 38 वर्षीय कार्यवाहक संपादक और बर्फ फैक्ट्री के मालिक राणा प्रताप बैरागी की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी और अब 5 जनवरी की रात सोमवार को देर रात एक हिंदू दुकानदार मोनी चक्रवर्ती की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जो पिछले 24घंटों में इस तरह की दूसरी घटना थी। कोई गारंटी नहीं है कि यह अमानवीयता, दरिंदगी और बर्बरता का सिलसिला यहीं थमेगा।

आपको बता दें कि ऐसी घटनाओं पर बंगलादेश की अंतरिम सरकार की चुप्पी उसकी नीयत में खोट का संकेत देती है जिस पर विश्व भर में चिंता व्यक्त की जा रही है। बांग्लादेश में जमात–ए–इस्लामी जैसी कट्टरवादी ताकतों तथा पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ने से वहां के लोगों में भारत विरोधी भावनाएं बढ़ गई हैं और सुरक्षा मामलों में सहयोग भी प्रभावित हुआ है। इस समय राजनीतिक अस्थिरता झेल रहा बांग्लादेश कट्टरपंथियों के दबाव में आकर आज आक्रामकता अराजकता और कानून व्यवस्था के सबसे बुरे दौर में पहुंच रहा है। जहां से लौटना और कानून व्यवस्था अराजकता पर नियंत्रण पाना अस्थिर सरकार के बूते से बाहर की बात होगी। आखिर भारत सरकार कब तक बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ की जा रही बर्बरता को नजरअंदाज कर सकती है?

सम्पादकीय

भारत की डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने वाला एक गेम चेंजर

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) परियोजना आजादी के बाद शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी रेल अवसंरचना योजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य माल ढुलाई के लिए उच्च क्षमता और आधुनिक तकनीक से लैस विशेष रेल कॉरिडोर तैयार करना है।इस परियोजना के माध्यम से भारतीय रेल तेज, सुरक्षित, भरोसेमंद और कम लागत वाली लॉजिस्टिक सेवाएं देकर माल परिवहन के क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी दोबारा बढ़ाना चाहती है। साथ ही, इस परियोजना से मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्कों के विकास को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी और पूरी आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में सुधार होगा।

करीब ?1.2 लाख करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत और 2843 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के दो मुख्य हिस्से हैंरू

पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर(ईडीएफसी)रू

यह 1337 किलोमीटर लंबा है। यह कॉरिडोर पंजाब के लुधियाना स्थित साहनेवाल से लेकर बिहार के सोननगर तक जाता है और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों से होकर गुजरता है।

पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्ल्यूडीएफसी)रू

यह 1506 किलोमीटर लंबा है। यह उत्तर प्रदेश के दादरी से लेकर मुंबई के पास जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) तक फैला हुआ है। यह हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर गुजरता है। कुल मिलाकर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) का मार्ग 7 राज्यों और 56 जिलों से होकर गुजरता है। यह जंगलों, वन्यजीव अभयारण्यों, मैंग्रोव क्षेत्रों और क्रीक इलाकों से भी होकर जाता है, जिससे इस परियोजना का निर्माण कार्य स्वाभाविक रूप से जटिल हो जाता है।

समय पर पूरा होने में आने वाली चुनौतियां

हालांकि इस परियोजना की शुरुआत 2008 में हुई थी, लेकिन कई बाध ाओं के कारण कई वर्षों तक काम की गति धीमी रही। मुख्य चुनौतियां इस प्रकार थींरू

लगभग 11,000 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण, जिसमें अवैध कब्जे और बने हुए ढांचों को हटाना शामिल था।

वन भूमि, वन्यजीव अभयारण्यों, मैंग्रोव क्षेत्रों, पेड़ों की कटाई और क्रीक (नाले) पार करने से जुड़े कानूनी अनुमतियां प्राप्त करना।900 से अधिक लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने के लिए रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) और रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) का निर्माण, जिनके लिए संयुक्त नक्शा स्वीकृति और रास्तों के लिए भूमि अधिग्रहण आवश्यक था।हाई टेंशन बिजली लाइनों, गैस और तेल पाइपलाइनों को स्थानांतरित करना।रक्षा विभाग, एनएचएआई, राज्य राजमार्ग प्राधिकरणों, सिंचाई विभाग से नहर पार करने की अनुमति और मिट्टी उधार लेने की स्वीकृति।कोविड के बाद ठेकेदारों पर पड़ा आर्थिक दबाव, जिससे नकदी की कमी हुई।निर्माण के लिए बिना किसी बाधा वाली भूमि उपलब्ध न होने से कार्य समय–सारिणी पर गंभीर असर पड़ा और परियोजना पर संभावित दावों का खतरा भी बढ़ गया।

प्रगति पोर्टल–निर्णायक मोड़

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से शुरू किया गया प्रगति पोर्टल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) परियोजना के लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ। इस पोर्टल के माध्यम से डीएफसी के अधिकारियों ने लंबे समय से लंबित समस्याओं को पूरे दस्तावेजों के साथ अपलोड किया। प्रगति पोर्टल की सबसे बड़ी ताकत इसकी पारदर्शिता और जवाबदेही थी। संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों और विभागों को यह साफ पता था कि कार्य की प्रगति पर सबसे ऊंचे स्तर पर, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी, निगरानी की जा रही है।जो मुद्दे वर्षों तक लगातार प्रयासों के बावजूद अटके रहे थे, वे कुछ ही हफ्तों में, और कई मामलों में तो कुछ दिनों के भीतर ही, सुलझा लिए गए। जहाँ तुरंत समाधान संभव नहीं था, वहाँ विभागों ने निश्चित समय–सीमा तय की और उसका सख्ती से पालन किया गया।

शासन और जवाबदेही की नई संस्कृति

प्रगति पोर्टल एक अत्यंत प्रभावी मंच के रूप में सामने आया, जिसके माध्यम सेः

परियोजनाओं की रियल–टाइम निगरानी संभव हुई

समस्याओं को एक साथ कई स्तरों तक तुरंत पहुँचाया जा सकाएक ही मंच से मंत्रालयों और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय हो पायाडीएफसी परियोजना में भी इसी तरह की एक आंतरिक निगरानी व्यवस्था लागू की गई। बड़े ठेकों की साप्ताहिक समीक्षा, नियमित स्थल निरीक्षण और तय किए गए लक्ष्यों की लगातार निगरानी सामान्य प्रक्रिया बन गई।चूंकि पोर्टल पर डाली गई सभी समय–सीमाएं दर्ज रहती थीं, इससे परियोजना टीम के भीतर अपने वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी और जवाबदेही की भावना भी मजबूत हुई।परियोजना क्रियान्वयन पर स्पष्ट प्रभाव

आस्था से टकरा गये स्टालिन

आप आस्था न रखें, यह अलग बात है लेकिन उससे टकरा जाएं तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। आस्था का तात्पर्य यहां दैवी शक्ति के प्रति विश्वास से है। बहुत लोग हैं जिनको विश्वास नहीं होता लेकिन जिनका यकीन होता है वे गलत कैसे हो गये? इसीलिए नास्तिकों से किसी का विरोध नहीं होता लेकिन आस्था पर चोट करने वालों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम. स्टालिन को इसीलिए अदालत की फटकार सुनने को मिली। मुख्यमंत्री स्टालिन किसी देवी–देवता में विश्वास रखते हैं, यह तो नहीं मालूम लेकिन कार्तिगई दीपक जलाने का विरोध करने पर उन्हें मद्रास हाईकोर्ट की लताड़ पड़ी है। राज्य की थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ियों के ऊपर पत्थर के खंभे पर दीपक जलाने वालों की आस्था मुरुगन पर है लेकिन वहीं पर मुस्लिम सम्प्रदाय के इबादतगाह की आपत्ति को मुख्यमंत्री स्टालिन ने महत्व दिया। निश्चित रूप से यह महत्य वोट की राजनीति के चलते दिया गया। राज्य में इसी साल विधान सभा के चुनाव भी होने हैं। माना जा रहा कि स्टालिन ने इसीलिए विरोध किया लेकिन अदालत की इस दलील का उनके पास कोई जवाब नहीं है। अदालत ने पूछा कि इबादतगाह के बगल में दीप जलाने से मुसलमानों की इबादत में बाधा कैसे पड़ने लगी? यह मुद्दा राज्य में विधान सभा चुनाव के समय भी उठ सकता है। दरगाह बनाम मंदिर का विवाद सिसायी मुद्दा बन गया है। यह भगवान मुरुगन का पवित्र स्थल है। दक्षिण भारत का यह प्रकाश पर्व है।

मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ियों के ऊपर पत्थर के खंभे (दीपथून) पर कार्तिगई दीपम जलाने के आदेश को बरकरार रखा। साथ ही, राज्य की इस आशंका को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि इस रस्म से लोगों की शांति और सांप्रदायिक सदभाव बिगड़ सकता है। जस्टिस जी जयचंद्रन और केके रामकृष्णन की डिवीजन बेंच ने थिरुपरनकुंद्रम मुरुगन मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मदुरै डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मदुरै सिटी पुलिस कमिश्नर की अपीलों का निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया। बेंच ने सभी पार्टियों की डिटेल में दलीलें सुनने के बाद 18 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ये अपीलें 1 दिसंबर को सिंगल जज जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के पास किए गए ऑर्डर से उठी थीं, जिन्होंने कार्तिगई दीपम के मौके पर पहाड़ी की चोटी पर बने पत्थर के खंभे पर दीया जलाने के लिए निर्देश मांगने वाली एक पिटीशन को मंजूरी दी थी। हालांकि, सरकार के कानून–व्यवस्था की संभावित चिंताओं का हवाला देने के बाद ऑर्डर लागू नहीं किया गया। डिवीजन बेंच के सामने 2 मुख्य सवाल उठे थे। पहला कि क्या पत्थर के खंभे को हिंदुओं के लिए दीपदान माना जा सकता है, जिससे उन्हें कार्तिगाई दीपम रस्म के हिस्से के तौर पर दीया जलाने का हक मिल जाएगा? दूसरा कि क्या दीया जलाने की इजाजत देने से पास की मुस्लिम दरगाह के अधिकारों का उल्लंघन होगा या उन पर असर पड़ेगा? बेंच ने अपने फैसले में राज्य और दूसरे अपील करने वालों की कड़ी आलोचना की। बेंच ने कहा कि इस मजाक पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। कोर्ट ने कटाक्ष करते हुए कहा, 'पावरफुल राज्य यह दावा कर सकता है कि मंदिर की जमीन पर मंदिर द्वारा दीया जलाने से पब्लिक पीस में गड़बड़ी होगी? कोर्ट ने क ह ा कि ऐसी बात को माना नहीं जा सकता। जजों ने इस बात की भी आलोचना की। बहस के दौरान सरकार की दलील को शरारत वाला बताया गया है। उन्होंने कहा कि पत्थर के खंभे दरगाह का बताना मजाक है। कोर्ट ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया।तमिलनाडु में मंदिर की पहाड़ी के एक स्तंभ पर दीप जलाने की इजाजत देने वाले जज के खिलाफ महाभियोग के लिए विपक्षी सांसदों ने प्रस्ताव दिया। दरअसल, थिरुपरनकुंदरम पहाड़ी भगवान मुरुगन के छह पवित्र आश्रयों अरुपदई वीडु में से एक है। इस पहाड़ी पर एक प्राचीन चट्टान काटकर बनाया गया गुफानुमा मंदिर बना है। यह तमिलनाडु भर के श्रद्धालुओं के लिए लंबे समय से एक तीर्थस्थल रहा है। इसके समीप दरगाह भी है। मंदिर और दरगाह की मात्र 3 किलोमीटर की दूरी को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच पहाड़ी पर अधिकार को लेकर तनाव होता रहा है। मंदिर और दरगाह ने 1920 में पहली बार पहाड़ी पर कानूनी अधिकार को लेकर चुनौती दी थी। एक सिविल कोर्ट ने पहले फैसला दिया था कि दरगाह से जुड़े कुछ क्षेत्रों को छोड़कर यह पहाड़ी सुब्रमण्यस्वामी मंदिर (देवस्थानम) की है। इस फैसले ने पहाड़ी के स्वामित्व का निपटारा तो कर दिया, लेकिन इसमें रीति–रिवाजों, परंपराओं या दीपम की परंपरा का उल्लेख नहीं किया गया था।इसके बाद मंदिर के पवित्र स्तंभ में दीप (कार्थीगाई दीपम लैंप) जलाने की इजाजत देने वाला जस्टिस जीआर स्वामीनाथन का फैसला आया।

बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग नोटिस की आलोचना की। उन्होंने जस्टिस स्वामीनाथन के फैसले को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में चुनाव हैं, इसलिए डीएमके के लोग वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मंदिर में दीप जलाने में क्या गलत है? कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा होनी चाहिए, अनुमति होनी चाहिए। हर मामले को आप महाभियोग तक ले आएंगे तो यह मजाक बन जाएगा।बता दें कि थिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी को भगवान मुरुगन के छह पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। यहां एक बड़ा प्राचीन पत्थर और मंदिर है। इस मंदिर का दर्शन करने के लिए दूर–दूर से लोग आते हैं। इस पहाड़ी के पास एक दरगाह भी है। दरगाह और मंदिर के बीच विवाद भी काफी पुराना है। पहाड़ी किसकी है इसका विवाद 1920 से चला आ रहा है। इस पहाड़ी के मालिकाना हक को लेकर 1920 में पहला केस दर्ज हुआ। इस मामले की सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दरगाह के आस–पास के क्षेत्र को छोड़कर इस पहाड़ी पर अधिकार सुब्रमण्यास्वामी मंदिर का है। पहाड़ी पर दीप उत्सव या धार्मिक अनुष्ठान होना है कि नहीं, कोर्ट ने इस बार में कोई फैसला नहीं सुनाया।बीते कई दशकों तक यह मामला शांत रहा लेकिन 1994 में एक श्रद्धालु ने दीप प्रज्वलन अनुष्ठान को पारंपरिक स्थान से स्थानांतरित कर दरगाह के समीप पहाड़ी के ऊपर करने का आदेश देने की मांग की। आगे साल 1996 में हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में दीपम को मंडपम के समीप पारंपरिक स्थान पर प्रज्वलित करने की इजाजत दी। 2014 में, मद्रास हाईकोर्ट की दो जजों की पीठ ने दीपाथुन पर दीपक जलाने के खिलाफ निर्णय दिया था। इस बार, मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ में कार्तिगाई दीपम जलाने की अनुमति मांगने के लिए एक नई याचिका दायर की गई थी।

कार्तिगई दीपम तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक दक्षिण भारतीय प्रकाश पर्व है, जो भगवान मुरुगन को समर्पित है। मुरुगन को कार्तिकेय और सुब्रमण्यम स्वामी भी कहा जाता है, जो भगवान शिव और पार्वती के पुत्र हैं। तमिल माह कार्तिगई की पूर्णिमा के साथ मनाया जाने वाला यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय, समृद्धि के आह्वान और बुरी आत्माओं को दूर भगाने के प्रतीक के रूप में दीप जलाकर मनाया जाता है।

अंजाम-ए-गुलिस्तां क्या होगा

नेशनल मेडिकल कमीशन ने मंगलवार देर रात जम्मू–कश्मीर के रियासी में स्थित श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की मान्यता रद्द कर दी। इस खबर को पढ़ते ही शौक बहराइची का मशहूर शेर याद आ गया कि–बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम–ए–गुलिस्तां क्या होगा।। देश में पहले से अच्छे उच्च शिक्षा संस्थानों की भारी कमी है। धार्मिक स्थलों के निर्माण, सौंदर्यीकरण, रख–रखाव पर अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, सरकार में बैठे लोगों का रोजमर्रा का खर्च लाखों में होता है, फिजूल के प्रचार कार्यक्रमों में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन जब उच्च कोटि के अस्पतालों और शिक्षा संस्थानों के निर्माण और उन्नयन की बारी आती है तो सरकार के पास धन की कमी दिखाई जाती है। छात्रों को पढ़ने और शोध कार्यों के लिए आसानी से धन मुहैया कराने की जगह सरकार का ध्यान शिलान्यासों और हरी झंडी दिखाने में लगा रहता है। ऐसे में एक मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर देना ऐसा फैसला है, जिस पर सिर ही पीटा जा सकता है।मान्यता रद्द करने के पीछे मानकों का पालन न होने को कारण बताया जा रहा है। लेकिन असल मुद्दा यही है कि पिछले काफी वक्त से इस मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों को मिले दाखिले पर हिंदू संगठन आपत्ति जता रहे थे और इसके लिए बाकायदा संघर्ष समिति बनाकर आंदोलन किया जा रहा था। दरअसल इस मेडिकल कॉलेज के पहले एमबीबीएस बैच के 50 छात्रों में से 42 मुस्लिम, एक सिख और केवल 8 हिंदू छात्र जम्मू क्षेत्र से होने की जानकारी सामने आई थी। अधिकतर छात्र कश्मीर से थे। इसी पर हिंदूवादी संगठन हंगामा मचा रहे थे कि जब मेडिकल कॉलेज हिंदुओं के दिए दान से चल रहा है, तो उसमें मुस्लिम छात्रों को दाखिला क्यों दिया जा रहा है। आंदोलनकारी बाकायदा कॉलेज को बंद करने की मांग ही कर रहे थे। जो अब शायद मानकों के बहाने से पूरी कर दी गई है।जम्मू–कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस फैसले पर निराश होते हुए कहा है कि उन बच्चों ने मेहनत करके सीट हासिल की है, यह किसी का उन पर एहसान नहीं है– न मेरा, न यूनिवर्सिटी का। उन्होंने परीक्षा पास करके सीट प्राप्त की है। अब अगर आप उन्हें वहां नहीं पढ़ाना चाहते, तो कहीं और उनका इंतजाम कीजिए। वे किसी के एहसान पर नहीं आए हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीमारी का इलाज करने के बजाय, मरीज को बिना किसी गलती के दंडित किया जा रहा है। अधिक चिंताजनक बात यह है कि यदि एसएमवीडी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के साथ ऐसा किया जा सकता है, तो इसे अन्य जगहों पर भी दोहराया जा सकता है, जिससे मेहनती युवाओं का भविष्य गंभीर खतरे में पड़ जाएगा।गौरतलब है कि नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने एसएमवीडी से एमबीबीएस कोर्स चलाने की इजाजत वाले आदेश को वापस ले लिया है। इसके बाद से ही छात्र और उनके शिक्षक चिंतित हैं। फैकल्टी सदस्यों ने आरोप लगाया कि हिंदुत्ववादी संगठनों के आंदोलन ने एनएमसी के फैसले को प्रभावित किया है। बता दें कि 2 जनवरी को एनएमसी ने संस्थान का औचक निरीक्षण किया और महज 15 मिनट में फैसला लिया कि 2025–26 सत्र के लिए एमबीबीएस कोर्स चलाने के लिए दी गई अनुमति वापस ली जाती है। एक बयान में कहा गया है कि यह फैसला अधोसंरचना में गंभीर कमियों के आधार पर लिया गया है।मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटर के अनुसार, पिछले दो हफ्तों में खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लिनिकल मटीरियल की कमी और फैकल्टी एवं रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी की कई शिकायतें मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। बोर्ड ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार कॉलेज में शिक्षकों की संख्या करीब 39 प्रतिशत कम थी। ट्यूटर, डेमोंस्ट्रेटर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर भी 65 प्रतिशत कम मिले। मरीजों की संख्या भी निर्धारित मानकों से काफी कम मिली। दोपहर 1 बजे तक ओपीडी में सिर्फ 182 मरीज मौजूद थे, जबकि कम से कम 400 मरीज होने चाहिए थे। अस्पताल में केवल 45 प्रतिशत बेड पर मरीज थे, जबकि मानक 80 प्रतिशत का है। आईसीयू में भी क्षमता से आधे मरीज थे। इसके अलावा कई विभागों में लैबोरेटरी हीं थीं, रिसर्च लैब नहीं थी, लेक्चर थिएटर मानकों के अनुरूप नहीं थे और लाइब्रेरी में सिर्फ 744 किताबें थीं जबकि 1500 किताबें जरूरी हैं। केवल 2 ऑपरेशन थिएटर काम कर रहे थे जबकि कम से कम 5 थिएटर होने चाहिए थे। पैरा–क्लीनिकल विषयों के लिए उपकरण भी पर्याप्त नहीं थे।मान लिया कि इस रिपोर्ट के मुताबिक संस्थान में ढेर सारी कमियां थीं, लेकिन उन कमियों को दूर किया जाना चाहिए या संस्थान ही बंद होना चाहिए। एनएमसी का कहना है कि जिन छात्रों का दाखिला हो चुका है, उनका वर्ष बर्बाद नहीं होगा और उन्हें जम्मू और कश्मीर के दूसरे मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों में समायोजित किया जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में छात्रों को जिस मानसिक तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, उसका निदान क्या है, यह भी मोदी सरकार को बताना चाहिए। हालांकि इस सरकार से अब शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी अच्छा करने की उम्मीद नहीं रखना चाहिए। एक मेडिकल कॉलेज के बंद होने पर जो लोग ढोल बजाकर, मिठाई बांटकर खुशियां मनाएं, वो असल में देश को शिक्षित होते देखना ही नहीं चाहते हैं। उनका मकसद केवल हिंदुत्व का भगवा झंडा बुलंद करना है, फिर इसके लिए देश का भविष्य खतरे में पड़े, उन्हें परवाह नहीं है। भाजपा जम्मू और कश्मीर इकाई के अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा है कि, हम नेशनल मेडिकल कमीशन के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के फैसले का स्वागत करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनुमति रद्द करके छात्रों का भविष्य सुरक्षित किया है। अब जो लोग कॉलेज की मान्यता रद्द होने को छात्रों का भविष्य सुरक्षित होना मान रहे हैं, वो देश को किस तरह विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, समझा जा सकता है।

बीबीएयू में 10 से 12 जनवरी तक तीन दिवसीय विश्वविद्यालय दिवस समारोह, 'बाबासाहेब के विचार एवं विकसित भारत की संकल्पना' होगी थीम

लखनऊ(संवाददाता)। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में 10 से 12 जनवरी तक तीन दिवसीय विश्वविद्यालय दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष समारोह की थीम 'बाबासाहेब के विचार एवं विकसित भारत की संकल्पना' निर्धारित की गई है। कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन 10 जनवरी को होगा, जिसकी अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल करेंगे। उद्घाटन सत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार एवं चाणक्य विश्वविद्यालय, बैंगलोर के प्रो. के.वी. राजू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में बीबीएयू के पूर्व कुलपति प्रो. बी. हनुमैया तथा मुख्य वक्ता के तौर पर पूर्व सलाहकार, शिक्षा, योजना आयोग, भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति एवं राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. फुरकान कमर भाग लेंगे।विश्वविद्यालय दिवस समारोह की रूपरेखा साझा करते हुए कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने कहा कि तीन दिवसीय कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आने वाले 22 वर्षों का एक स्पष्ट, दूरदर्शी और प्रभावी रोडमैप तैयार करना है। उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप योजनाओं और उद्देश्यों का स्पष्ट निर्धारण आवश्यक है, ताकि भारत की प्रगति में विश्वविद्यालय और अकादमिक जगत सार्थक योगदान दे सकें। वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचारों ने शिक्षा सहित कई क्षेत्रों को नया स्वरूप दिया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का भी महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ऐसे में एआई और एनईपी–2020 की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए रोजगार के अवसर बढ़ाने, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और पाठ्यक्रमों को अधिक कौशल–आधारित बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों और शोध कार्यों को सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप विकसित किया जाएगा।कुलपति ने एनईपी–2020 पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि इस नीति ने उच्च शिक्षा संस्थानों में बहुविषयक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने, भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन तथा आउटकम–बेस्ड लर्निंग के माध्यम से विद्यार्थियों और संस्थानों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने भारत रत्न बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर के स्वप्न को साकार करने के लिए 'एक्सीलेंस और इक्विटी' के विजन को अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि शिक्षा ही समाज में सकारात्मक बदलाव की सबसे मजबूत आधारशिला है। उन्होंने संस्थागत विकास योजना के संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत, समरसता, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी, स्वभाषा, स्वबोध, कर्तव्यबोध और परिवार प्रबोधन जैसे घटकों की महत्ता को रेखांकित किया। साथ ही युवाओं तक स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों को पहुंचाने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि सशक्त युवा ही सशक्त भारत की नींव हैं।समारोह के दूसरे दिन 11 जनवरी को विश्वविद्यालय द्वारा 'विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि हेतु सामाजिक परिवर्तन का आह्वान' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल करेंगे। संगोष्ठी में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. ईश्वर शरण विश्वकर्मा, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान लखनऊ के कार्यकारी अध्यक्ष प्रो. सदानन्द प्रसाद गुप्त, अम्बेडकर फाउंडेशन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सदस्य डॉ. चमन लाल बंगा, आयोजन समिति बीबीएयू के चेयरपर्सन प्रो. राजशरण शाही, इतिहासवेत्ता एवं सामाजिक चिंतक संजय हर्ष, तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के भू–विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रो. ध्रुव सेन सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे। इस दौरान समरसता, स्वभाषा के संरक्षण, स्वदेशी और स्वबोध की भावना, पर्यावरण संरक्षण, कर्तव्यबोध और परिवार प्रबोधन जैसे विषयों पर गहन विचार–विमर्श किया जाएगा।तीसरे दिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एवं कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल करेंगे। इस अवसर पर प्रो. राजशरण शाही, सामाजिक कार्यकर्ता कश्मीरी लाल, इनक्यूबेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप बीबीएयू के कंसल्टेंट डॉ. मनोज जोशी तथा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रो. विनोद सोलंकी आमंत्रित रहेंगे। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा, जो रचनात्मकता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश देगा।

भाजपा राज में कानून व्यवस्था ध्वस्त, महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा सवालः अखिलेश यादव

लखनऊरू(संवाददाता) समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर हैं और महिलाएं व बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा सरकार के सारे दावे झूठे साबित हो चुके हैं और 'जीरो टॉलरेंस' का नारा अब शून्य में बदल गया है। अखिलेश यादव ने मेरठ में मां पर हुए कथित कातिलाना हमले और बेटी को उठाकर ले जाने की घटना को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार अपराधियों को संरक्षण देते–देते ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है, जहां से उसकी वापसी संभव नहीं है, क्योंकि अपराधी उनके राज खोल देंगे। उन्होंने कहा कि जब सरकार से उम्मीद ही खत्म हो जाए, तो उससे बुरा कुछ नहीं होता और यह सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है।अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि महिला अपराध और साइबर क्राइम के मामलों में उत्तर प्रदेश देश में सबसे ऊपर पहुंच गया है, जिसकी सीधी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोजाना महिलाओं के साथ हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं और हर पंद्रह दिन में दुष्कर्म जैसी शर्मनाक वारदातें हो रही हैं। पूरे प्रदेश में हत्या, लूट और बलात्कार की घटनाएं आम हो गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार झूठे विज्ञापनों के जरिए चाहे जितने दावे कर ले, लेकिन सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता और प्रदेश की जनता 2027 में महिला सुरक्षा के झूठे दावे करने वाली सरकार को सत्ता से बाहर कर देगी।सपा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार की भ्रष्टाचार और लूट की नीति के कारण प्रदेश में तरह–तरह के अपराध पनप रहे हैं। जो अपराध पहले स्थानीय समझे जा रहे थे, उनकी परतें खुलने पर वे राज्यव्यापी, फिर राष्ट्रव्यापी और अब अंतरराष्ट्रीय स्तर के सामने आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसे बढ़ावा मिला है और भाजपा शासन में 'महा–माफिया राज' कायम है, जो लोगों के घरों तक घातक रूप में पहुंच रहा है। अरबों की काली कमाई में सत्ताधारी दल की भागीदारी का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इसी वजह से भाजपा राज में जनता त्रस्त और अभागी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा अपनी अंतिम पारी का अंतिम चरण खेल रही है और उसके ओवर अब पूरे हो चुके हैं, पूरी टीम मैच खत्म होने से पहले ही ऑल आउट होने जा रही है।

कौशांबी में आकार ले रहा अंतरराष्ट्रीय स्तर का बुद्ध थीम पार्क, आध्यात्मिक पर्यटन को मिलेगी नई पहचान

लखनऊ(संवाददाता)। कौशांबी की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पहचान को नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग एक महत्वाकांक्षी परियोजना को तेजी से मूर्त रूप दे रहा है। कोसम इनाम गांव में निर्माणाधीन बुद्ध थीम पार्क को युद्धस्तर पर विकसित किया जा रहा है, जहां भगवान बुद्ध के जीवन, दर्शन और करुणा के संदेश को कलात्मक मूर्तियों और संरचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। लगभग 11 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित हो रहा यह थीम पार्क 22.93 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है, जिसे मौजूदा वर्ष के अंत तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी।पर्यटन मंत्री ने बताया कि सरकार की परिकल्पना के अनुरूप इस बुद्ध थीम पार्क को देश–विदेश से आने वाले बौद्ध अनुयायियों और पर्यटकों के लिए एक विशिष्ट आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना न केवल कौशांबी को वैश्विक बौद्ध पर्यटन सर्किट में सशक्त स्थान दिलाएगी, बल्कि क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ–साथ रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी।कौशांबी में निर्माणाधीन बुद्ध थीम पार्क को तेलंगाना के नागार्जुन सागर स्थित प्रसिद्ध बुद्धवनम की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। इस परिसर में ध्यान और सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ी अनेक सुविधाएं प्रस्तावित हैं। पार्क के अंतर्गत विभिन्न मुद्राओंकृधर्मचक्र मुद्रा, अभय मुद्रा और भूमिस्पर्श मुद्राकृपर आधारित एक विशेष ध्यान केंद्र स्थापित किया जाएगा। परियोजना का प्रमुख आकर्षण बुद्धचरित वनम होगा, जहां भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा को जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक मूर्तियों के माध्यम से सजीव रूप में दर्शाया जाएगा।इसके साथ ही जातक म्यूरल गैलरी, ध्यान वनम और स्तूप गैलरी जैसे विशिष्ट जोन विकसित किए जा रहे हैं, जो आगंतुकों को भगवान बुद्ध के जीवन–दर्शन और आध्यात्मिक संदेश से गहराई से जोड़ेंगे। विशेष रूप से स्तूप गैलरी में श्रीलंका, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, म्यांमार, नेपाल, तिब्बत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान सहित विभिन्न देशों के 13 प्रतिष्ठित स्तूपों की प्रतिकृतियां स्थापित की जाएंगी। साथ ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रमुख बौद्ध स्थलों को भी इस परिसर में समावेश किया जाएगा, जिससे यह बुद्ध थीम पार्क राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक समग्र सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में अपनी अलग पहचान बना सकेगा।प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति अमृत अभिजात ने बताया कि कौशांबी का बुद्ध थीम पार्क विरासत संरक्षण और उच्च गुणवत्ता वाली पर्यटन अधोसंरचना के समन्वय का एक सशक्त उदाहरण होगा। भगवान बुद्ध से कौशांबी का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संबंध इसे अंतरराष्ट्रीय महत्व का स्थल बनाता है। विभाग का प्रयास है कि आधुनिक सुविधाओं के साथ देश–विदेश से आने वाले पर्यटकों को बेहतर और समृद्ध पर्यटन अनुभव प्राप्त हो, जिससे उत्तर प्रदेश वैश्विक बौद्ध पर्यटन मानचित्र पर और अधिक मजबूती से उभरे।

मिशन शक्ति के तहत महिला हेल्प डेस्क कर्मियों का विशेष प्रशिक्षण, संवेदनशील और प्रभावी पुलिसिंग पर जोर

लखनऊ(संवाददाता)। महिला सुरक्षा को और अधिक प्रभावी, संवेदनशील और परिणामोन्मुखी बनाने की दिशा में पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई। पुलिस आयुक्त अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला हेल्प डेस्क कर्मियों के लिए एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 9 जनवरी 2026 को डालीगंज स्थित कमिश्नरेट कार्यालय में किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय अपर्णा कुमार के मार्गदर्शन में, पुलिस उपायुक्त महिला अपराध एवं सुरक्षा ममता रानी चौधरी के नेतृत्व तथा सहायक पुलिस आयुक्त महिला अपराध सौम्या पाण्डेय के पर्यवेक्षण में संपन्न हुआ।प्रशिक्षण कार्यक्रम दो चरणों में आयोजित किया गया। पहला सत्र प्रातः 11 बजे से दोपहर 12रू30 बजे तक तथा दूसरा सत्र दोपहर 1 बजे से अपराह्न 2रू30 बजे तक चला। इसमें लखनऊ कमिश्नरेट के सभी थानों से 100 से अधिक महिला हेल्प डेस्क कर्मियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य महिला पीड़िताओं को अधिक संवेदनशील, भरोसेमंद और प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कर्मियों के कानूनी ज्ञान, व्यवहारिक कौशल और मनोवैज्ञानिक समझ को सुदृढ़ करना रहा।प्रशिक्षण के दौरान महिला सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें दहेज से संबंधित अपराध, पति द्वारा क्रूरता, यौन उत्पीड़न, भारतीय न्याय संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों तथा पॉक्सो अधिनियम की जानकारी दी गई। साथ ही शिकायत दर्ज करने की संवेदनशील प्रक्रिया, पीड़िता से संवाद स्थापित करने की कला, विश्वास अर्जित करने, एफआईआर अथवा एनसीआर दर्ज करते समय सावधानियों और आपातकालीन सहायता प्रक्रिया पर विशेष बल दिया गया।मनोवैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण में आघात से गुजर रही महिला पीड़िताओं को मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के तरीकों की भी जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त महिला कल्याण विभाग, चाइल्डलाइन, वन–स्टॉप सेंटर सखी, विधिक सेवा प्राधिकरण जैसे संस्थानों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई, ताकि पीड़िताओं को त्वरित और समग्र सहायता मिल सके। तकनीकी दृष्टि से कर्मियों को हेल्पलाइन सॉफ्टवेयर, शिकायत ट्रैकिंग सिस्टम और सोशल मीडिया के सकारात्मक एवं जिम्मेदार उपयोग के बारे में भी प्रशिक्षित किया गया। महिला हेल्प डेस्क पर प्राप्त शिकायतों के सुव्यवस्थित डाटा प्रबंधन और नियमित रिपोर्टिंग को भी प्रशिक्षण का अहम हिस्सा बनाया गया।वरिष्ठ अधिकारियों ने महिला हेल्प डेस्क कर्मियों को यह संदेश दिया कि उनकी भूमिका केवल एक शिकायत दर्ज करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें पीड़ित महिलाओं के लिए मित्र, मार्गदर्शक और सहायक की भूमिका निभानी है। अधिकारियों ने कहा कि महिला हेल्प डेस्क महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और न्याय की आशा का प्रतीक हैं और इन्हें पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संचालित किया जाना चाहिए।लखनऊ पुलिस ने स्पष्ट किया कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही इस वर्ष प्रत्येक थाने की महिला हेल्प डेस्क की कार्यप्रणाली का ऑडिट और निगरानी के लिए एक मजबूत प्रणाली विकसित की जाएगी, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।यह प्रशिक्षण कार्यक्रम लखनऊ पुलिस की उस निरंतर प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसके तहत एक ऐसा सुरक्षित वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है, जहां महिलाएं निर्भय होकर और सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। मिशन शक्ति के माध्यम से पुलिस बल के भीतर संवेदनशीलता और दक्षता का एक नया मानक स्थापित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत डालीगंज क्रासिंग पर महिला सुरक्षा को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान

लखनऊ(संवाददाता)। महिला सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों को सशक्त बनाने की दिशा में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा लगातार जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज 9 जनवरी 2026 को थाना मदेयगंज की पुलिस टीम द्वारा डालीगंज क्रॉसिंग पर महिला अपराधों की रोकथाम और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान चलाया गया।इस दौरान थाना मदेयगंज की टीम ने राहगीरों, महिलाओं, छात्राओं और बच्चों को मिशन शक्ति के उद्देश्यों की जानकारी दी तथा महिला सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न सरकारी व्यवस्थाओं और सहायता प्रणालियों के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम के अंतर्गत एंटी रोमियो टीम, पिंक बूथ, पिंक मोबाइल और महिला शक्ति केंद्र की भूमिका को समझाते हुए पम्पलेट वितरित किए गए, ताकि अधिक से अधिक लोग इन सुविधाओं से अवगत हो सकें और आवश्यकता पड़ने पर बिना संकोच सहायता प्राप्त कर सकें।पुलिस टीम ने बताया कि महिला सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसके अंतर्गत हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहयोग और संरक्षण प्रदान किया जाता है। पिंक बूथ को विशेष रूप से एक सुरक्षित आश्रय और सहायता केंद्र के रूप में विकसित किया गया है, जहां घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन शोषण अथवा किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाएं तत्काल सहायता प्राप्त कर सकती हैं।मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में 54 थानों पर मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इन केंद्रों पर निरीक्षक, अतिरिक्त निरीक्षक, उपनिरीक्षक की तैनाती की गई है। इनका उद्देश्य थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्याओं का त्वरित, संवेदनशील और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है।कार्यक्रम के दौरान करीब 25 से 30 महिलाओं, छात्राओं और बच्चों को महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों, उनके कानूनी अधिकारों और सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई। साथ ही महिला पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्डलाइन 1098, टोल–फ्री सिटीजन कॉल सेंटर 1076, अग्निशमन सेवा 101, एम्बुलेंस सेवा 102 और 108, आपातकालीन सेवा 112 तथा साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 जैसे महत्वपूर्ण नंबरों की उपयोगिता के बारे में भी विस्तार से समझाया गया।इसके अतिरिक्त साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और यूपी कॉप ऐप के माध्यम से मिलने वाली डिजिटल सुविधाओं की जानकारी भी साझा की गई, जिससे महिलाएं और आम नागरिक ऑनलाइन शिकायत, त्वरित सहायता और सुरक्षा से जुड़ी सेवाओं का लाभ उठा सकें।पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मिशन शक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और डिजिटल सुरक्षा जैसे विषयों पर जानकारी देना है,।

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में दो अहम बैठकों का आयोजन, चुनावी वर्ष को लेकर रोडमैप और संगठन मजबूती पर मंथन

लखनऊ(संवाददाता)। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज दो महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन किया गया। पहली बैठक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्यों की हुई, जबकि दूसरी बैठक मनरेगा कोऑर्डिनेटर, एसआईआर कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों, जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों तथा फ्रंटल, विभाग और प्रकोष्ठों के चेयरमैनों के साथ संपन्न हुई। ये दोनों बैठकें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पाण्डेय की गरिमामयी उपस्थिति में तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की अध्यक्षता में आयोजित की गईं। बैठक के आरंभ से पूर्व अविनाश पाण्डेय और अजय राय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया।बैठक में उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और बृजलाल खाबरी के साथ–साथ राष्ट्रीय सचिव एवं सहप्रभारी धीरज गुर्जर, राजेश तिवारी, तौकीर आलम, प्रदीप नरवाल, सुप्रिया श्रीनेत, संयुक्त सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मनोज त्यागी, राज्यसभा में उपनेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी, केएल शर्मा, उज्जवल रमण सिंह, इमरान मसूद, तनुज पुनिया, पूर्व सांसद पीएल पुनिया, कुँवर दानिश अली, एपी गौतम, रवि वर्मा, पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और नकुल दुबे सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी, विवेक बंसल, संजय कपूर, पूर्व विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह, निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक प्रसाद, निवर्तमान प्रदेश महासचिव संगठन अनिल यादव, पिछड़ा वर्ग विभाग कांग्रेस उत्तर प्रदेश के चेयरमैन मनोज यादव, अंकित तिवारी, अनस रहमान, संजय दीक्षित और मनीष हिंदवी भी बैठक में शामिल रहे।बैठक को संबोधित करते हुए अविनाश पाण्डेय ने कहा कि यह चुनावी वर्ष है और पार्टी के सामने पंचायत चुनाव, एमएलसी चुनाव और विधानसभा चुनाव जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी चुनावों को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत और ठोस रोडमैप तैयार करना होगा तथा प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर मजबूत संगठन खड़ा करना समय की मांग है।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने अपने संबोधन में कहा कि आने वाले 100 दिनों के भीतर प्रदेशभर में 30 से अधिक संविधान संवाद रैलियों का आयोजन किया जाएगा। इन रैलियों के माध्यम से जनता की समस्याओं को मजबूती के साथ उठाया जाएगा और संविधान तथा लोकतंत्र की रक्षा का संदेश जन–जन तक पहुंचाया जाएगा। संगठन सृजन पर बोलते हुए राजेश तिवारी ने कहा कि पिछले आठ महीनों की मेहनत से बूथ स्तर तक एक सशक्त संगठन तैयार किया गया है और इसी संगठन के बल पर कांग्रेस 2027 के रण में उतरेगी।बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि आगामी 12 जनवरी को प्रियंका गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी मंडलों पर प्रेस वार्ताएं आयोजित कर 100 दिन की कार्ययोजना घोषित की जाएगी। इस संबंध में आराधना मिश्रा मोना ने बताया कि पहले प्रेस वार्ता होगी और उसके बाद प्रियंका गांधी के जन्मदिन से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।पंचायत चुनाव पर बोलते हुए धीरज गुर्जर ने कहा कि यह एक ऐसा जमीनी चुनाव है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव की दिशा और दशा तय करेगा। वहीं एसआईआर प्रक्रिया को लेकर तौकीर आलम ने कहा कि प्रदेश में जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, उन्हें लेकर पार्टी ने एसआईआर कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है। उन्होंने कहा कि पिछले चार नवंबर से की गई मेहनत से आगे के एक महीने में दोगुनी मेहनत करनी होगी, ताकि वैध मतदाताओं के नाम जुड़वाए जा सकें और भाजपा को फर्जी वोटर बनवाने से रोका जा सके।

ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियमःए.के. शर्मा

भदोही लखनऊ (संवाददाता)। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री तथा जनपद भदोही के प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) कृ विकसित भारत जी–राम–जी अधिनियम को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने इस नए अधिनियम को ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा कि इससे ग्रामीण श्रमिकों, किसानों और मेहनतकश वर्ग के जीवन में व्यापक और सकारात्मक परिवर्तन आएगा।प्रेस वार्ता में ए.के. शर्मा ने बताया कि इस अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने, पलायन रोकने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने में मील का पत्थर साबित होगा। यह कदम सरकार की ग्रामीण समाज के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।मंत्री ने कहा कि विकसित भारत जी–राम–जी अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बेरोजगारी भत्ता अब केवल कागजी प्रावधान न रहकर एक वास्तविक और प्रभावी कानूनी अधिकार बन गया है। पूर्ववर्ती महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम में अनेक शर्तों और जटिलताओं के कारण बेरोजगारी भत्ता मिल पाना लगभग असंभव था, जबकि नए अधिनियम में सभी अनावश्यक प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। अब यदि किसी श्रमिक द्वारा कार्य की मांग किए जाने के बाद निर्धारित समय के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो बेरोजगारी भत्ता स्वतः देय होगा।उन्होंने यह भी बताया कि मजदूरी भुगतान की व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया है। यदि किसी कारणवश मजदूरी के भुगतान में विलंब होता है, तो प्रत्येक विलंबित दिन का मुआवजा मजदूरी के साथ श्रमिक को दिया जाएगा। इससे श्रमिकों के शोषण पर रोक लगेगी और उन्हें उनके परिश्रम का पूरा लाभ समय पर मिल सकेगा।ए.के. शर्मा ने कहा कि इस अधिनियम के अंतर्गत विकास कार्यों की योजना अब ऊपर से थोपे जाने के बजाय ग्राम स्तर पर ही तय की जाएगी। ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायतें अपनी 'विकसित ग्राम पंचायत योजना' तैयार करेंगी, जिसमें ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य होगी। इससे स्थानीय जरूरतों के अनुरूप कार्यों का चयन होगा ।

राजस्व बढ़ाने के लिए नगर निगम का बड़ा कदम, 10 व 11 जनवरी को भी खुले रहेंगे जोनल कार्यालय और कर काउंटर

लखनऊ(संवाददाता)। नगर निगम लखनऊ ने वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले राजस्व संग्रहण को तेज करने के उद्देश्य से एक अहम निर्णय लिया है। नगर आयुक्त के आदेश पर आगामी शनिवार और रविवार, 10 व 11 जनवरी 2026 को नगर निगम के सभी जोनल कार्यालय और कर काउंटर खोले रखने का निर्णय लिया गया है। इन दोनों दिनों में कर काउंटर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित रहेंगे, जिससे नागरिकों को कर भुगतान में अतिरिक्त सुविधा मिल सके।वर्तमान वित्तीय वर्ष के समापन में अब तीन माह से भी कम समय शेष है। ऐसे में नगर निगम प्रशासन द्वारा गृहकर और जलकर की वसूली बढ़ाने तथा निर्धारित राजस्व लक्ष्य की पूर्ति के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सार्वजनिक अवकाश के दिन भी कर संबंधी कार्य किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक करदाता अपने बकाया कर का भुगतान कर सकें।नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन दोनों दिनों में सभी जोनल कार्यालयों में भवन स्वामियों से संबंधित कर निर्धारण, डाटा फीडिंग, संशोधन, आपत्तियों का निस्तारण और कर जमा करने से जुड़े सभी कार्य किए जाएंगे।

विनय अग्रवाल बने ओलंपिक एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष

लखीमपुर खीर(संवाददाता)ओलंपिक एसोसिएशन लखीमपुर इकाई की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में खेल की महत्व पर विशेष प्रकार डाला गया। कार्यक्रम में पदाधिकारी ने खेल की उपलब्धियां के विषय में जानकारी दी और लखीमपुर जिला अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों का चुनाव भी किया गया।

शहर के मशहूर व्यापारी विनय कुमार अग्रवाल को जिले की कमान सौंपते हुए उन्हें जिलाध्यक्ष का पद का कार्यभार सौंपा गया। जिला ओलंपिक एसोसिएशन महासचिव शारिफ तारा और कोषाध्यक्ष विवेक कुमार ने नव चयनित जिलाध्यक्ष विनय कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में संगठन को सकारात्मक रूप से देखते हुए महासचिव तारा ने कहा कि संगठन न सिर्फ आगे बढ़ेगा बल्कि खेलों को विशेष रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक जिले के खिलाड़ियों जनपद से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक का मंच प्रदान करने वाली एक मात्र खेल संस्था, जिला ओलंपिक एसोसिएशन का चेयरमैन मनोनीत किया गया है। इस अवसर पर तमाम खेल प्रेमियों ने खुशी व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है। बताते चलें कि विनय अग्रवाल एक सोशल वर्कर और खेल प्रेमी व्यक्ति है। खेलो के क्षेत्र में खिलाडियों को हरसंभव सहयोग भी करते हैं। उम्मीद है कि ये खेल और खिलाड़ियों के हितों के लिए कार्य करते रहेंगे। जिला ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।

सालाना उर्स परम्परागत तरीके से पूरी अकीदत के साथ मनाया

खीरी(संवाददाता) मरकजी दरगाह में हजरत हाफिज मोहम्मद मुश्ताक अलमारूफ छेदा मियाँ रह0 का सालाना उर्स परम्परागत तरीके से पूरी अकीदत के साथ मनाया गया। इस मौके पर बीती रात आस्ताने पर चिरागां किया गया और देर रात तक महफिले समां का आयोजन हुआ। अगली सुबह शुक्रवार को कुरआन ख्वानी हुई और बाद में महफिले समां हुई। जुमा के दिन सवेरे जामा मस्जिद में मीलाद की नूरानी महफिल सजाई गई जिसमें खतीबे अहले बैत सय्यद सलमान रिजवी ने नबी और आले नबी की शान में तकरीर की और जुमा की नमाज के पहले जामा मस्जिद में इस दरगाह के ही चश्मो चिराग मौलाना सय्यद अमीन मियाँ ने नूरानी खिताब किया और जुमा की नमाज के बाद फातेहा ख्वानी हुई जिसमें दरगाह शरीफ के खानवादे सय्यद मिनहाज मियाँ, सय्यद शाह मुमताज मियाँ, मौलाना सय्यद अमीन मियाँ, सय्यद वकार मियाँ और बड़े मखदूम साहब खैराबादी के सज्जादा नशीन सय्यद मदनी मियाँ, अमृतापुर गाँव स्थित हजरत साबिर मियाँ की दरगाह के सज्जादा हजरत मुश्शन, दरगाह की जामा मस्जिद के इमाम हाफिज सईदुर्रह्मान, मौलाना रईस समेत बहुत से अकीदतमंदों ने फातेहा में शिरकत किया। बाद में बड़े पैमाने पर लंगर बांटा गया। दरगाह के साहिबे सज्जादा सय्यद मुमताज मियाँ की देख रेख में आयोजित इस 291 वाँ सालाना उर्स के मौके पर मुकामी व बाहरी हजारों अकीदतमंदों ने आस्ताने पर हाजिरी देकर फैज हासिल किया और साहिबे सज्जादा से मुलाकत करके दस्तबोसी की। पूर्व वर्षो की तरह इस बार भी सालाना उर्स के मौके पर मेहमानों के खाने पीने और ठहरने का माकूल इंतिजाम किया गया था।

वाहन चोर गिरोह का सदस्य गिरफ्तार

बांदा(संवाददाता)पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरतारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गिरोह बनाकर वाहनों की चोरी करने वाले गैंगस्टर एक्ट के एक अन्य वांछित अभियुक्त (गैंग सदस्य) को गिरतार कर लिया गया है। गिरतार अभियुक्त एक संगठित वाहन चोर गिरोह का सक्रिय सदस्य है, जो अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दो पहिया व चार पहिया वाहनों चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर में गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजी.त किया गया था और वांछित चल रहा था जिसे थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को उसके घर पिपरी खेरवा थाना बिसण्डा से गिरतार किया गया। पकड़े गए अभियुक्तों में अरविन्द पुत्र रामसुमेर निवासी पिपरी खिरवां थाना बिसंडा है। पकड़ने वाली पुलिस टीम में बलराम सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली, नगर कां0 संदीप कुमार, कां0 पवन शामिल रहे।

सीएम युवा उद्यमी योजना से जुड़कर हजारों लोग बने आत्मनिर्भर

- पिछले एक वर्ष में जिले में 1412 लोगों ने लिया इस योजना का लाभ

बांदा(संवाददाता)मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से जुड़कर जनपद में हजारों लोग आत्मनिर्भर बने हैं और जनवरी से अब तक 1412 लाभार्थियों ने इस योजना का लाभ लिया है और अपना उद्योग व सेवा क्षेत्र को बढ़ाने का काम किया है। वही इस योजना में लोगों की काफी रुचि भी देखने को मिल रही है और लगातार लोग इस योजना का लाभ लेने के लिए जुड़ रहे हैं। योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का लोन लाभार्थियों को दिया जाता है। जिसके जरिए लाभार्थी अपना उद्योग या सेवा क्षेत्र शुरू कर सकते हैं। वही सरकार के द्वारा 10: की सब्सिडी भी दी जाती है। वहीं इस योजना की खास बात यह है कि बिना ब्याज व बिना गारंटी के ही 5 लाख रुपये तक का लोन लाभार्थी को दिया जाता है और इसको 4 साल में लाभार्थी को चुकाना होता है। वहीं जिला उद्योग विभाग के द्वारा लोगों को इस योजना का लाभ मिले इसके प्रति प्रेरित करने का भी काम किया जा रहा है। प्रदेश में 10 वर्षों में 10 लाख लोगों को लाभ देने का है लक्ष्य दरअसल मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान भी कहा जाता है और सरकार का लक्ष्य है कि 10 वर्षों में इस योजना के जरिए 10 लाख लोगों को लाभ दिया जाए यानी कि प्रत्येक वर्ष एक लाख लाभार्थियों को लाभ देने का सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है। जिससे कौशल प्रशिक्षण प्राप्त 21 से 40 वर्ष के युवा उद्योग या सेवा संबंधी उद्दम स्थापित कर स्वरोजगार युक्त बन सके। जिसके क्रम में 24 जनवरी से शुरू हुई इस योजना में बांदा में 31 दिसंबर 2025 तक 1412 लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया गया है। जिसमें 369 महिला लाभार्थी भी शामिल हैं जिन्होंने अपना उद्योग शुरू किया है या अपने सेवा क्षेत्र को बढ़ाया है। लाभार्थियों ने कई और लोगों को दिया रोजगार इस योजना से जुड़कर शहर के गायत्री नगर मोहल्ले के रहने वाले गुरु प्रसाद ने कोचिंग सेंटर की शुरुआत की है तो वही बड़ोखर खुर्द गांव की रहने वाली हीरामणि ने क्लाउड किचन खोला है और टिफिन सर्विस के जरिए कमाई कर रही हैं। वहीं अमलोर गांव की रहने वाली मेघा सिंह ने ब्यूटी पार्लर खोला है तो वही नगनेधी गांव की रहने वाली प्रीति ने आटा चक्की व स्पेलर उद्योग लगाया है। वहीं ऐला गांव के रहने वाले महंतलाल ने माटी कला उद्योग की शुरुआत कर दी है और इन लोगों ने अपने साथ अन्य लोगों को भी जोड़ा है और रोजगार देने का काम किया है। इसी तरह अन्य लाभार्थियों ने भी इस योजना से जुड़कर अपने उद्योग या सेवा क्षेत्र की शुरुवात की है। इस योजना में जुड़कर 369 महिलाएं भी बनी स्वरोजगार युक्त जिला उद्योग विभाग के उपायुक्त गुरुदेव रावत व जिला प्रबंधक राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि यह योजना 24 जनवरी 2025 से शुरू हुई थी और 31 मार्च 2025 तक 291 लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाया गया था। जिसमें 211 पुरुष व 80 महिला लाभार्थी शामिल हैं। वहीं 1 अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक 1121 लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाया गया है। जिसमें 832 पुरुष व 289 महिला लाभार्थी शामिल हैं। इन्होंने बताया कि बांदा के लोग इस योजना से लगातार जुड़ रहे हैं और लगातार पंजीकरण कर रहे हैं और अभी तक लगभग तीन हजार लोगों ने इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करा लिया है।

बोलेरो की टक्कर से बाल-बाल बचा युवक, चौराहे पर मचा हड़कंप

सीतापुर(संवाददाता) जनपद के सिधौली थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एक बड़ा हादसा होते–होते टल गया। लालपुर चौराहे पर पैदल जा रहे एक युवक को तेज रतार बोलेरो ने जोरदार टक्कर मार दी, लेकिन गनीमत रही कि युवक की जान बच गई।

जानकारी के अनुसार महमूदाबाद की ओर से आ रहा युवक पंकज, निवासी ग्राम सरसौली, पैदल सिधौली की तरफ जा रहा था। दोपहर करीब एक बजे जैसे ही वह लालपुर चौराहे पर पहुंचा, तभी महमूदाबाद की दिशा से आ रही एक अज्ञात बोलेरो ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी तेज थी कि युवक सड़क की पटरी पर जा गिरा। हादसे को देख आसपास मौजूद लोगों में अफरा–तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत दौड़कर युवक को उठाया और उसकी हालत देखी। आश्चर्यजनक रूप से युवक को कोई गंभीर चोट नहीं आई, जिससे सभी ने राहत की सांस ली। हादसे के बाद बोलेरो चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और बोलेरो का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक वाहन का कोई सुराग नहीं मिल सका। स्थानीय लोगों ने लालपुर चौराहे पर तेज रतार वाहनों पर नियंत्रण लगाने और पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके।

गोला कारिडोर की धीमी रफ्तार पर 3.35 करोड़ रुपए की पेनल्टी तय

- भुगतान से पहले जुर्माने की कटौती, डीएम ने प्रमुख सचिव पर्यटन को लिखा पत्र
- तीन ठेकेदारों पर कुल 3.35 करोड़ का लिक्विडेटेड डैमेज तय

लखीमपुर खीरी(संवाददाता) गोला गोकर्णनाथ स्थित प्राचीन शिव मंदिर को पर्यटन मानचित्र पर चमकाने की योजना पर ठेकेदारों की सुस्ती भारी पड़ गई है। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली गोला कॉरिडोर परियोजना में निर्माण कार्य की रतार थमती देख डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। जाँच समिति और तकनीकी परीक्षण के बाद तीन ठेकेदारों पर 3.35 करोड़ रुपये से अधिक का लिक्विडेटेड डैमेज लगाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। स्थलीय निरीक्षण में एसडीएम गोला सहित अन्य अधिकारियों ने पाया कि निर्माण स्थल पर न श्रमिक पर्याप्त हैं, न ही काम में अपेक्षित तेजी। यूपी प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) यूनिट 14 लखनऊ द्वारा कराए जा रहे कार्य की अनुबंधित पूर्णता तिथि 15 मार्च 2026 है लेकिन मौजूदा हालात में समय पर कॉरिडोर का पूरा होना मुश्किल नजर आ रहा है। चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई कि इतनी अहम परियोजना में देरी के बावजूद समयवृद्धि का प्रस्ताव तक सक्षम प्राधिकारी को नहीं भेजा गया, जिसे प्रशासन ने गंभीर लापरवाही माना है। उल्लेखनीय है कि श्रावण मास के दौरान गोलागोकर्णनाथ शिव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं कांवड़ियों का आगमन होता है। यदि कॉरिडोर निर्माण कार्य श्रावण मास से पूर्व पूर्ण नहीं होता है तो शांति एवं कानून–व्यवस्था बनाए रखने में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है। तकनीकी आख्या में जुर्माने की मुहर जाँच समिति की रिपोर्ट में गोला कॉरिडोर निर्माण की भौतिक प्रगति अत्यंत धीमी पाई गई है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार पहले ठेकेदारों पर 10 प्रतिशत तक जुर्माना प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद यूपीपीसीएल के परियोजना प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण का तकनीकी परीक्षण लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय खंड से कराया गया। अधिशासी अभियंता की आख्या में अनुबंध संख्या 109 (मेसर्स रीना सिंह) पर 8 प्रतिशत यानी लगभग 1.45 करोड़ रुपये, अनुबंध संख्या 110 (मेसर्स नारायन एसोसिएट्स) पर 6 प्रतिशत यानी लगभग 1.04 करोड़ रुपये तथा अनुबंध संख्या 111 (मेसर्स नारायन एसोसिएट्स) पर 5 प्रतिशत यानी लगभग 86 लाख रुपये का लिक्विडेटेड डैमेज अधिरोपित किया जाना उचित बताया गया। भुगतान से पहले कटेगी पेनल्टी डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश को पत्र लिखा है कि कार्यदाई संस्था यूपीपीसीएल को भुगतान करते समय 3.35 करोड़ पेनल्टी की राशि काटकर भुगतान किया जाए, ताकि अनुबंध की शर्तों के अनुसार जुर्माना वसूली और परियोजना की समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित हो सके।

कड़ाके की ठंड में समाजसेवा के साथ जनसमस्याओं से रुबरु हुए प्रवीण

सीतापुर(संवाददाता)जनपद में गुरुवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव एवं लहरपुर विधानसभा प्रभारी प्रबीण कुमार सिंह ने कड़ाके की ठंड के बीच समाजसेवा और जनसंपर्क अभियान चलाया। विकास खंड सकरन क्षेत्र की ग्राम पंचायत मानपुर शिकरी के मजरा सोनावां, क्योटाना, हर्दोपट्टी, सैदापुर सहित अन्य गांवों में पहुंचकर उन्होंने गरीबों, बुजुर्गों, महिलाओं एवं दिव्यांगजनों को कंबल वितरित किए और लोगों से सीधे संवाद किया। जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों ने सकरन से सेमरावा मार्ग की बदहाल स्थिति को प्रमुख समस्या के रूप में उठाया। लोगों ने बताया कि सड़क अत्यंत जर्जर होने के कारण आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही कई पात्र दिव्यांगों और गरीब परिवारों ने मुख्यमंत्री आवास योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ अब तक न मिलने की बात भी रखी। प्रदेश महासचिव प्रबीण कुमार सिंह ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं को लेकर शीघ्र ही जिला प्रशासन को अवगत कराया जाएगा और समाधान के लिए ठोस पहल की जाएगी। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा और जनसमस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करना ही उनकी प्राथमिकता है। इस दौरान प्रबीण कुमार सिंह ने यह भी कहा कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाएगा। जिलाध्यक्ष ललित सिंह ने बताया कि आगामी चुनाव को लेकर पार्टी जल्द ही रणनीति तैयार करेगी और इसके लिए शीघ्र ही बैठक आयोजित की जाएगी। जनसंपर्क और समाजसेवा कार्यक्रम के दौरान जिलाध्यक्ष ललित सिंह, विकास खंड सकरन के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रमुख रूप से मनोज कुमार यादव, अरोज गिरी, प्रदीप कुमार यादव, गुड्डू भार्गव, संतोष रस्तोगी, नसीम गाजी, रामसागर यादव, रामपाल यादव, शिवकुमार, श्यामू अवस्थी सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

ग्राम पंचायत चुनाव की बयार

प्रधान पद को लेकर गांव-गांव सियासी सरगर्मी

अटरिया, सीतापुर (संवाददाता) प्रदेश में प्रस्तावित ग्राम पंचायत चुनावों की आहट के साथ ही ग्रामीण राजनीति ने रतार पकड़ ली है। सिधौली विकास खंड के अटरिया थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में प्रधान पद को लेकर माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंगता नजर आ रहा है। गांवों की गलियों से लेकर चौपालों तक अब विकास, वादों और दावेदारों की चर्चा आम हो चली है। अलाव के किनारे रणनीति इन दिनों ग्रामीण इलाकों में चाय की दुकानों और सर्द रातों में जलते अलावों के आसपास चुनावी चर्चाओं का दौर जारी है। कहीं पुराने चुनावों के अनुभव साझा हो रहे हैं तो कहीं नए उम्मीदवार अपनी रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। हर बैठक में एक ही सवाल गूंज रहा है। अटरिया थाना क्षेत्र की गुलरिया, मऊ, हीरपुर, बिरसिंहपुर, टिकौली, रानुआपारा, जाजौर, अंबरपुर, कठवा, पिर्थीपुर, अलाईपुर, ससेना, कुवरपुर, लहुरीवान, नयागांव सहित कई ग्राम पंचायतों में प्रधान पद के दावेदारों ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। कोई घर–घर जाकर समर्थन मांग रहा है तो कोई छोटे–छोटे कार्यक्रमों के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा हुआ है। वादों और दावों की राजनीति उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिए नए–नए तरीके अपना रहे हैं। कहीं विकास कार्यों का लेखा–जोखा पेश किया जा रहा है तो कहीं भविष्य की योजनाओं का खाका खींचा जा रहा है। सड़क, नाली, बिजली, पानी, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे चुनावी बहस के केंद्र में हैं। मतदाता भी दिखा रहे खास रुचि ग्राम पंचायत के मतदाता भी इस बार चुनाव को लेकर काफी सजग नजर आ रहे हैं। बुजुर्ग अपने अनुभव के आधार पर चर्चा कर रहे हैं, युवा वर्ग विकास और रोजगार को लेकर सवाल उठा रहा है, जबकि महिलाएं भी पंचायत में अपनी भागीदारी और सुविधाओं को लेकर खुलकर राय रख रही हैं। जैसे–जैसे नजदीक आएगा चुनाव, और तेज होगी राजनीति कुल मिलाकर अटरिया थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में प्रधान पद को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में जैसे–जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, वैसे–वैसे गांवों की राजनीति और भी दिलचस्प और रोचक रूप लेने की पूरी संभावना है।

हाईवे से हटवाई अवैध पार्किंग, 82 वाहनों का ई-चालान

फतेहपुर(संवाददाता) जनपद को जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट (शून्य मृत्यु दर वाला जिला) घोषित करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह के निर्देशन में सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। बीते गुरूवार की मध्यरात्रि में पुलिस द्वारा हाईवे पर व्यापक स्तर पर अभियान चलाया गया।विशेष अभियान के तहत सीसी टीम के सहयोग से कोतवाली, हुसैनगंज, थरियांव, खागा एवं मलवां थाना क्षेत्रों में संबंधित थाना प्रभारियों की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। अभियान का नेतृत्व यातायात प्रभारी लाल जी सविता द्वारा किया गया। पुलिस टीम ने हाईवे पर अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटवाकर यातायात को सुचारु कराया। कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे व हाईवे पर खड़े 82 वाहनों का ई–चालान किया गया, जो दुर्घटनाओं का कारण बन सकते थे। पुलिस ने मौके पर मौजूद वाहन चालकों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में हाईवे पर वाहन खड़ा करना दंडनीय अपराध है और दोबारा नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में हो रही अनावश्यक जनहानि को रोकना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि वे यातायात नियमों का पालन करें और पुलिस का सहयोग करें। पुलिस प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि आगे भी हाईवे पर अवैध पार्किंग, ओवरलोडिंग, तेज रतार और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध इसी तरह की सघन कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि सड़क हादसों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके।

टाउन हाल से अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई तेज, सपा कार्यालय पर संकट

- नगर पालिका के नोटिस से मचा राजनीतिक हलचल, सपा ने कोर्ट जाने का किया ऐलान

सीतापुर(संवाददाता) नगर के ऐतिहासिक टाउन हॉल परिसर में वर्षों से चले आ रहे अवैध कब्जों को हटाने की दिशा में नगर पालिका परिषद ने सख्त रुख अपना लिया है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी (सपा) कार्यालय को खाली कराने के निर्देश दिए जाने से जिले की राजनीति में हलचल मच गई है। नगर पालिका की ओर से बुधवार रात सपा कार्यालय सहित अन्य कब्जेदारों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर परिसर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि तय समय सीमा के भीतर कब्जा न हटा तो ऐसी स्थिति में प्रशासन द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के अनुसार तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल ने 15 जनवरी 2005 को टाउन हॉल परिसर की नजूल भूमि मात्र 100 रुपये वार्षिक किराए पर समाजवादी पार्टी को आवंटित की थी लेकिन आवश्यक वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन न होने के चलते यह आवंटन 14 अप्रैल 2005 को ही निरस्त कर दिया गया था। इसके बावजूद बीते लगभग 20 वर्षों से उक्त भूमि पर सपा कार्यालय संचालित होता रहा, जिसे अब नगर पालिका प्रशासन अवैध कब्जा मान रहा है। नगर पालिका ने इस मामले में सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव के साथ–साथ भाजपा नेता संजीव गुप्ता उर्फ टिंचू की मां मिथलेश गुप्ता समेत कुल छह लोगों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि टाउन हॉल नगर की सार्वजनिक संपत्ति है और उस पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने साफ शब्दों में कहा कि नजूल भूमि पर किया गया कब्जा अवैध है। कब्जेदारों को 15 दिन का समय दिया गया है, इसके बाद प्रशासन कठोर कार्रवाई करेगा। वहीं सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि भूमि का विधिक तरीके से आवंटन हुआ था और 99 वर्षों के लिए रजिस्ट्री कराकर कार्यालय का निर्माण किया गया था। उन्होंने कहा कि नोटिस का जवाब पार्टी स्तर से दिया जाएगा और न्याय के लिए कोर्ट की शरण ली जाएगी। टाउन हॉल परिसर से अवैध कब्जे हटाने की यह कार्रवाई आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है, जिससे सीतापुर की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में हलचल और बढ़ने के आसार हैं।

डीएम ने निर्माणाधीन कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का किया निरीक्षण

- दो एकेडमिक ब्लाक व हॉस्टल बिल्डिंग का जायजा लेकर दिए निर्देश

फतेहपुर।(संवाददाता) जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह ने भिटौरा विकास खण्ड में एक करोड़ से अधिक की लागत से निर्माणाधीन परियोजना कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण कर निर्माणाधीन विद्यालय में दो एकेडमिक ब्लॉक एवं हॉस्टल बिल्डिंग का जायजा लिया। कार्यदाई संस्था के अधिशाषी अभियंता ने अवगत कराया कि एकेडमिक ब्लॉक में तीन लैब, तीन कमरे चार क्लास रूम बनाए गए है। उन्होंने निर्माणाधीन लैब को देखा और अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि लैब की खिड़कियों को अच्छे से साफ कराते हुए फैटिंग कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने एनसीसी स्टाफ, गेम रूम का निरीक्षण कर बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि इनडोर गेम का समान गेम रूम में रखे। इस दौरान उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम संबंधी जानकारी प्राप्त की। अधिशाषी अभियंता ने अवगत कराया कि जल निकासी का प्रबंधन स्टैण्डर्ड डिजाइन के आधार पर तैयार किया गया है। जिसमें दोनों ब्लॉक की जल निकासी सम्मिलित रूप से वाटर टेबल रिचार्ज में एकत्र होगी। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि यह सुनिश्चित कर लें कि कहीं पर भी जलभराव की स्थिति न उत्पन्न हो, यदि कही पर आशंका होती है तो उसका प्रस्ताव तैयार करें। उन्होंने हॉस्टल बिल्डिंग में ग्राउंड लोर पर बने कोर्टयार्ड का निरीक्षण कर उसके स्लोप को मानक के अनुरूप बनाने के आवश्यक निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त प्रथम लोर पर निर्मित कमरों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने समस्त ब्लाकों में निर्माणाधीन वॉशरूम को अच्छी फिनिशिंग के साथ साफ सुथरा बनाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। अधिशासी अभियंता ने अवगत कराया कि 15 फरवरी तक कार्य पूर्ण हो जाएगा। जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि आस–पास के क्षेत्रों में ड्रॉप आउट हुए बच्चों को चिन्हीकरण का कार्य अभी से शुरू करा दे और परियोजना का भ्रमण कर गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है तो उसे अवगत कराएं। सभी कस्तूरबा विद्यालय में एक ले आउट बनवाए जिसमें किचेन गार्ड, खेल का मैदान तथा यदि पास में सरकारी जमीन है तो उसके स्कूल के उद्देश्य हेतु उपयोग में लाने हेतु शामिल करे। साथ ही यह भी निर्देशित किया कि यदि कही पर कस्तूरबा विद्यालय तैयार होकर हैंड।

कोतवाल धौरहरा रविन्द्र सोनकर ने बताया कि अनुमति नहीं है आवश्यक कार्रवाई की जाएगी

(मनोज मिश्र)

धौरहरा खीरी। जनपद लखीमपुर–खीरी में घाघरा व शारदा नदियों के बीचोबीच पलिया निघासन व धौरहरा तहसीलो का क्षेत्र आता है और इस सबमें वन रेंज धौरहरा का क्षेत्र दोनों नदियों के बीच के भू भाग में करीब दो दर्जन से अधिक हिसंक जंगली जीवों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जंगलों से निकल कर तराई क्षेत्र में डेरा डाले जंगली हिसंक जीव कभी कभी आम आदमी को नुकसान पहुंचाने के साथ आम लोगों को दर्शन देते रहते हैं।हालांकि वन विभाग के जिम्मेदार पिजंडा लगाने तक सीमित रहते हैं।हिंसक जंगली जानवरो के लिए तराई क्षेत्र वरदान साबित हो रहा है क्योंकि कृषिक भू भाग होने के चलते यहां केला,गन्ना,गेहूं,धान,उरद,मंसूर के साथ भारी मात्रा में सब्जी की फसलें भी उगाई जाती है।क्षेत्र में मौजूद नदियो का कछार,बह रहे नाले व गन्ना,केला लगे खेत जंगली जानवरों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। इनमें हाथी जैसे बड़े जानवर फसलें नष्ट कर देते हैं तथा क्षेत्र में कभी कभार हिसंक जानवरों के हमले से लोग असमय काल के गाल में समा जा रहे हैं जिसके बाद प्रशासनिक मशीनरी पीड़ित परिवार को सिर्फ आहेतुक सहायता राशि देकर मामले को रफा दफा कर देती है।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, ४० वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी २/३७६ रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ० प्र० से प्रकाशित।
सम्पादक
आरती पाण्डेय
ek-
9807059191- 9026560178
Email-
adbhutsamachar@gmail.com
adbhutsamachar@hotmail.com
सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।